राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की फिर मिली धमकी

इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का ई-मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर धमकी मिली है। बीते चार दिन में यह दूसरा मौका है, जब हाईकोर्ट में बम धमाका करने की धमकी दी गई है। इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए इस मेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की बात कही गई है। ई-मेल की जानकारी मिलने ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। वहीं न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद कर दी।

राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं।

- **बम की धमकी के बाद सोमवार को पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया, न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद की, जो कि 2 बजे बाद पुनः शुरू हुई**

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई। वहीं हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला गया। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि बदमाश वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन के कई प्रकार होते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और मैन पावर है। उसका इस्तेमाल करके आरोपियों को जल्दी ही ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही कुछ कामयाबी मिलेगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर मजाक की सी स्थिति बन गई है। बीते डेढ़ माह में हाईकोर्ट को तीन बार बम से उडाने के मेल मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच एजेंसियां अभी तक यह तक मालूम नहीं कर पाई हैं कि ई-मेल कहां से आया है। हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है और कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाता है। जिससे एक ओर भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होती है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि डढ़ माह में ही तीसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलना गंभीर है। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इन दोनों ईमेल की जांच करवानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे है।

पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोर्ट परिसर की पूरी तलाशी लेने के बाद क्लीन चिट दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे बाद से केसों की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुबह बम की धमकी मिलने के चलते अदालतों में सुनवाई नहीं हुई और हजारों प्रकरण प्रभावित हुए।

मुख्यमंत्री ने सुनीं राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में लोगों की समस्याएं

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सचिवालय में दौरा करते हुए अचानक राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन सेंटर 181 पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दो कॉलर्स नवलगढ़ (झुन्झुनूं) के सुधीर और कोटपूतली-बहरोड़ के नेमीचंद से बात कर उकी समस्याओं का भी तुरंत समाधान करवाया।

- **181 पर आ रही समस्याओं की बढ़ाई जाए मॉनिटरिंग : भजनलाल शर्मा**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया और परिवादियों की समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब राजस्थान संपर्क 181 पर समस्याएं सुन रहे थे तो एक कॉल पर नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर ने बताया कि उनके घर के पास साव की ढाणी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। परंतु सड़क के बीच में एक पोल आ रहा है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उस पोल को हटाने के लिए निवेदन किया। जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित कलक्टर ने पोल हटवाया।

इसी प्रकार एक अन्य शिकायतकर्ता नेमीचंद निवासी गोकलपुर गांव, वार्ड नंबर 29 (कोटपूतली-बहरोड़) ने मुख्यमंत्री को फोन पर बताया कि गोकलपुर गांव में वार्ड नंबर 29 में नाले की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी निकलकर सड़क पर भरा हुआ है। जिससे आवागमन में लोगों को समस्या आ रही है तथा बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने इस नाले की जल्द से जल्द सफाई कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आदेश पर संबंधित कलक्टर ने नाले की तुरंत सफाई करवाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 181 हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर आ रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटैण्ड किया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया।

आधुनिक और भारतीय शिक्षा के समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा शिक्षा बोर्ड : डॉ. एन.पी. सिंह

प्रयागराज। एएमए कन्वेंशन सेंटर प्रयागराज में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा पद्धित को पुनर्जीवित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय स्थापित करना है। आज देश को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों में आत्मगौरव, भारतीयता, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टि दोनों का विकास कर सके। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने प्रयागराज में संगोष्ठी को संबोधित किया।

डॉ. सिंह ने बताया कि बोर्ड के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, गीता, जैन और बौद्ध दर्शन, भारतीय शूरवीरों की कथाएँ, संवैधानिक मूल्य, गुरुकुल परंपरा और आधुनिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी को संतुलित रूप से जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में भारत के लगभग 120 महान नायकों की जीवनगाथाओं को भी शामिल किया है। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल नौकरी योग्य नहीं बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाएगी। बोर्ड का पाठ्यक्रम यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप भी विकसित किया गया है। यह बोर्ड के समकक्ष है, यह कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों को मान्यता देती है । कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता ले सकते हैं।

विशिष्ट अतिथियों में संयुक्त शिक्षा निदेशक राम नारायण विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव मेजर डॉ. हर्ष कुमार उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी भगवान सिंह भी कार्यक्रम में सहभागी रहे। कार्यक्रम का संचालन बृज मोहन ने किया।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्र खोलेगी भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करेगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कॅरियर परामर्श जैसी सुविधाएं मिल सके। यह पहल राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के समर्पित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विकास, शिक्षा और युवा सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

- **प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली 1274 पंचायतें चिन्हित**
- **इन जगहों पर ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कॅरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम होंगे**

ज्ञात रहे कि अटल ज्ञान केन्द्रों में ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी पुस्तकें, कॅरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सुविधा होगी। पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1274 केंद्रों को चिन्हित कर इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

पिछले दो वर्षों में भजनलाल सरकार ने युवा प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना इसी दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो ग्रामीण युवाओं को शहरों के समकक्ष अवसर प्रदान करेगा। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। अटल ज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की स्वीकृति प्रदान की गई है। करीब 232 करोड़ रुपए से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

‘नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण हितैषी’

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है।

निवेशकों की मांग पर एन.सी.आर. में औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराएगा रीको

उद्योगों की स्थापना के लिए बीडा 209 हैक्टेयर भूमि रीको को आवंटित करेगा

जयपुर (कासं)। "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024" के उपरांत विभिन्न उद्यमियों और औद्योगिक ग्रुप्स ने एनसीआर क्षेत्र में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की मंशा जाहिर थी। उनकी इस मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने अविलंब भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके उपरांत बीडा द्वारा लगभग 209 हैक्टेयर भूमि रीको को उपलब्ध कराई जायेगी। इस भूमि आवंटन से एक ओर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शीघ्रता से भूमि उपलब्ध करायी जा सकेगी, दूसरी ओर बीडा को लगभग 110 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति भी होगी, जिसका उपयोग बीडा द्वारा क्षेत्र के विकास एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। राज्य सरकार के इस कदम से राज्य में औद्योगिक माहौल विकसित करने और 350 करोड़ बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी।

- **रीको द्वारा जयपुर के जगतपुरा स्थित अपैरल पार्क में भी किया जाएगा औद्योगिक विकास**

औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से रीको और जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपैरल पार्क, जगतपुरा से संबंधित लंबे समय से चल रही भूमि समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। रीको द्वारा मुख्य महल रोड पर अपैरल पार्क की स्थापना वर्ष 2014 में लगभग 122 एकड़ पर की गई थी, जिसमें टैक्सटाइल एवं अपैरल उत्पादों के लिये ही औद्योगिक भूमि का आवंटन किया गया था। खातेदारों द्वारा लंबे समय से उन्हें 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिए जाने की मांग की जा रही थी। जेडीए के पास खातेदारों की मांग अनुसार विकसित भूमि दिए जाने हेतु पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता देखते हुए रीको से अतिरिक्त भूमि की मांग की गई थी।

रीको ने एक एमओयू जेडीए के साथ निष्पादित कर मुख्य 160 फीट रोड पर 4.57 हैक्टेयर भूमि खातेदारों से विवाद का समाधान करने के उद्देश्य से जेडीए को हस्तांतरित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। जेडीए इस भूमि का उपयोग खातेदारों को दी जाने वाली विकसित वाणिज्यिक भूमि के रूप में कर सकेगा, जिसके लिये जेडीए ने आवश्यक कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी है। इस कदम से ना सिर्फ विभिन्न गतिविधियों के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि जयपुर के प्रमुख महल रोड पर अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे सेवा क्षेत्र इत्यादि के लिये भी भूमि उपलब्ध हो सकेगी। गारमेंट एवं अपैरल सेक्टर में मुख्य नियोजन महिलाओं का होता है, इसलिये यहां महिलाओं के लिये भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे और ग्लोबल कैपेबिलिटी क्षेत्र, को-वर्किंग सेंटर, वाणिज्यिक परिसर, होटल आदि के निर्माण से पढ़े लिखे युवाओं को भी आने वाले समय में उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के नए अवसर विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हो सकेंगे। इस कदम से उन काश्तकारों ने भी राहत की सांस ली है जो लंबे समय से अपनी भूमि के एवज में विकसित भूमि की मांग कर रहे थे।

शिक्षण संस्थानों के आसपास नशा तस्करों के 35 ठिकानों पर दबिश

जयपुर । एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शिक्षण संस्थानों (कोचिंग-कॉलेज) के पास स्टूडेंट्स को नशे की लत में धकेलने वालों के पैतीस से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर बाईस मामले दर्ज कर बाईस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 1 लाख 93 हजार 610 रुपए भी बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि काफी समय से जयपुर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों का अवैध व्यापार की शिकायते मिल रही थी, जिससे विद्यार्थी नशे की गिरफ्त में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इस सूचना पर महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार के निर्देशन में एटीएस-एएनटीएफ की पैतीस टीमें गठित कर जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस महानिरीक्षक एटीएस-एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि मादक पदार्थ तस्कर शिक्षण संस्थानों के पास विद्यार्थियों को मादक पदार्थ देकर नशे की आदत डाल रहे थे। यह एक गंभीर और अनैतिक कार्य है। जो विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। जहां गठित टीम के पुलिसकर्मियों को संबंधित शिक्षण संस्थानों की वर्दी पहना कर भेजा गया।

लेपर्ड के मूवमेंट के कारण एजी कॉलोनी में दिनभर रही दहशत

वन विभाग की टीम ने बजाज नगर क्षेत्र में सोमवार को सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु लेपर्ड हाथ नहीं लगा

जयपुर । राजधानी जयपुर के बजाज नगर स्थित एजी कॉलोनी में रविवार की देर शाम को लेपर्ड का मूवमेंट होता देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सोमवार को सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु टीम को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। रैज ऑफिसर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सोशल मीडिया से यह विडियो मिलने पर वन विभाग टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक लेपर्ड नहीं मिला है।

- **वन्य अधिकारियों का मानना है कि भोजन-पानी की तलाश में लेपर्ड आबादी क्षेत्र में पहुंचा होगा**

जानकारी के अनुसार लाल बहादुर कॉलोनी में रविवार को बजाज नगर एन्क्लेव, सरस्वती कॉलोनी और अनिता कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया। जहां लेपर्ड कभी घरों में घुसा,कभी गलियों से निकला। फुटेज वायरल होते ही कॉलोनियों में दहशत फैल गई। लोग सतर्क हो गए और वेलफेयर सोसायटी ने चेतावनी जारी कर दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लेकिन लेपर्ड हाथ नहीं आया। रेंज ऑफिसर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह एक वर्ष से भी कम उम्र का शावक है और अब मॉनिटरिंग टीमें लगातार निगरानी कर रही है। आशंका है कि शावक स्टेशन के पास नाले से होते हुए वापस जंगल की ओर चला गया। उसके जेएलएन रोड पार कर शिक्षा संकुल की ओर से आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से एमएनआईटी में भी लेपर्ड की मूवमेंट है।

अनिता कॉलोनी निवासी अरुण कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे बजाज नगर एन्क्लेव कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला को लेपर्ड का एक शावक दिखा। उसे देखते ही महिला ने शोर मचाया। जिस पर शावक वहां से भाग गया। इसकी जानकारी आसपास की कॉलोनियों में तेजी से फैल गई। कुछ देर बाद यह शावक सरस्वती कॉलोनी से होता हुआ अनिता कॉलोनी पहुंचा। यहां दो घरों में घुसा, जिसका मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन केसी अरुण प्रसाद की ओर से गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। टीम आधुनिक तकनीक, ट्रैकर्स और स्थानीय इनपुट की मदद से लेपर्ड के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। जानकारी के अनुसार यह पूरा जोन झालाना लेपर्ड सफारी की परिधि से जुड़ा हुआ है। जहां पर करीब 40 से अधिक लेपर्ड रहवास करते हैं। जहां से भोजन और पानी की तलाश में लेपर्ड आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर के कई हिस्सों में लेपर्ड की मूवमेंट की घटनाएं बढ़ने से वन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में पिछले एक महीने में शहर में कई बार लेपर्ड के रिहायशी इलाकों में आने की घटना हो रही है। इस दौरान लेपर्ड सिविल लाइंस, गुर्जर की घाटी, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, चांदपोल, मोती डूंगरी इलाकों में देखे गए हैं।

राजीविका ग्रामीण उद्यमता का सशक्त मॉडल : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का सोमवार को अवलोकन किया।

जयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सोमवार को सांगानेर के ठीकरिया स्थित राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फैडरेशन पहुंचे। जहां उन्होंने ब्लू पॉटरी एवं बगरू प्रिंट से जुड़ी लखपति दीदियों से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों के अनुभव जाने।

मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि राजस्थान की स्वयं सहायता समूहों की इन प्रेरणादायक कहानियों को प्रधानमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव ने महिलाओं द्वारा निर्मित विविध उत्पादों की विशेष प्रशंसा भी की। साथ ही सेनेटरी नैपकिन यूनिट का अवलोकन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि ग्रामीण महिलाएँ अपने कौशल एवं परिश्रम से पूर्णतः स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी बन रही हैं। राजीविका प्लेटफॉर्म ने महिलाओं में उद्यिमता को मजबूत आधार प्रदान किया है। राजीविका की महिलाए अपने उत्पाद सीधे ही बड़ी कंपनियों को बेच सकेगी उन्होंने आश्वासन दिया 'बायर सेलर मीट' को और व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा ।

सांगानेर में पहला राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार "आपणो अग्रणी राजस्थान" के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है।

- **विधि महाविद्यालय के भवन के लिए 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए**

इस महाविद्यालय में तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा विधि महाविद्यालय के भवन हेतु 4.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य के लिए टेण्डर जारी कर दिये जायेंगे। स्थाई भवन निर्मित होने तक अस्थाई तौर पर महाविद्यालय का संचालन शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जा रहा है।

विधि महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 19 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें सहायक आचार्य के सात, कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो तथा प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं बुक लिफ्टर के एक-एक पद शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित नवीन विधि महाविद्यालय युवाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। इससे युवा कानूनी शिक्षा ग्रहण कर न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकेंगे।